a heritage site and it needs to be protected. So, that is a separate question for a separate Ministry: Whether the UNESCO has rejected or turned back the Government of India's proposal to declare it as a 'World Heritage Site'. But if you have any knowledge of that, please inform the House.

Secondly, the question is ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN : Only one question please.

SHRI SITARAM YECHURY : Sir, the question is, why all the funds, which have been allocated, are not being properly supervised. There is an annual erosion in the Island, which is physically visible. Please remember, it is also the seat of a large number of religious headquarters of Assam. They keep moving upward and upward every year because their *Satras,* which are there, are being destroyed. This has created a lot of social problems also. So, please take adequate measures in this regard and please explain to the House as to why the funds are not being effectively utilized.

श्री हरीश रावत : सर, यह बात बार-बार उठी है, इसीलिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। उसके ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह बराबर इसको मॉनिटर करें और इसीलिए मिनिस्टर की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी में एक कमेटी भी constituted है।

जो इन चीजों को रेग्युलरली एग्जामिन करने का काम करती है, लेकिन सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए, मैं फिर से इस सारे मामले को देखूंगा। आपने जो यूनेस्को हैरिटेज साइट के प्रपोजल की बात कही है, राइट नाऊ मेरे पास उसके विषय में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, परंतु मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आपको सूचित कर दूंगा।

Utilization of funds

*223. DR. JANARDHAN WAGHMARE : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has recently warned the State Governments on inadequate utilization of funds lying with them under various flagship schemes;

(b) if so, whether most of the State Governments are not utilizing the Integrated Watershed Management Programme (IWMP) funds and thereby schemes are mostly affected;

(c) if so, the details of States which are not properly utilizing the funds allocated under various flagship schemes; and

(d) the action contemplated by government in this regard?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI JAIRAM RAMESH) : (a) to (d) A statement is placed on the table of the house.

Statement

(a) to (d) The State Governments and Union Territory Administrations are required to utilize the funds as per the Programme Guidelines and the Ministry regularly monitors utilization and advises State Governments on the need to improve systems and processes. In order to achieve the programme objectives including the utilization of funds, the Ministry of Rural Development regularly reviews all the programmes, including flagship programmes namely the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), and Indira Aawas Yojana (IAY) through various mechanism such as on-line Progress Reports, Performance Review Committee (PRC), Area Officer's Scheme, National Level Monitors (NLM), National Quality Monitors (NQM), Delivery Monitoring Unit (DMU), Outcome Budget Monitoring, Monitoring by programme-specific bodies like Central Employment Guarantee Council and other independent organizations and Vigilance and Monitoring Committees at the State/District level.

The Department of Land Resources is implementing the Integrated Watershed Management Programme (IWMP). Utilization of funds and unspent balance under IWMP is closely monitored through Steering Committee meetings, Regional Review Meeting, State Ministers conference, Chief Executive Officers Conference of State Level Nodal Agencies (SLNA), etc. The Operational Guidelines for release of Central assistance under IWMP has been revised on 13.6.2012 to better tackle the issue of unspent balances. As per the revised release mechanism, Central assistance is being released after deducting the unspent balance available with the States.

A Statement showing State-wise unspent balance under Flagship programmes including IWMP during 2011-12 is given in Statement-I.

Statement-I

State-wise and Programme-wise unspent Balance under flagship Programme and IWMP during 2011-12

(*Rs. in lakhs*)

Sl. No.	Name of State	MGNREGA (As on 31.03.2012)	IAY (As on 31.11.2012)	PMGSY (As on 01.04.2012)	IWMP (As on 31.10.2012)
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Pradesh	144985.62	0.00	44483.00	13085.00
2.	Arunachal Pradesh	748.00	1235.49	6091.00	1925.00
3.	Assam	8593.54	53816.06	75119.00	6269.00
4.	Bihar	62164.00	170121.24	119742.00	1283.00
5.	Chhattisgarh	42698.40	6032.55	82744.00	8852.00
6.	Goa	216.56	61.97	468.00	0.00
7.	Gujarat	16545.33	32554.72	-1789.00	56054.00
8.	Haryana	1873.90	1129.41	4287.00	2617.00
9.	Himachal Pradesh	15108.09	394.53	19483.00	10649.00
10.	Jammu and Kashmir	12766.48	3149.45	34501.00	1683.00
11.	Jharkhand	51801.96	20141.37	81494.00	2843.00
12.	Karnataka	39834.39	75550.79	-6660.00	31733.00
13.	Kerala	14269.32	13108.10	12409.00	2825.00
14.	Madhya Pradesh	193000.00	9424.55	64313.00	19303.00
15.	Maharashtra	16847.00	10089.64	44120.00	98579.00
16.	Manipur	2717.00	1298.27	2630.00	4632.00
17.	Meghalaya	2210.23	951.33	3731.00	718.00

1	2	3	4	5	6
18.	Mizoram	463.49	500.57	2257.00	130.00
19.	Nagaland	2337.36	1820.90	466.00	1127.00
20.	Orissa	33800.00	38113.49	109753.00	10625.00
21.	Punjab	4296.93	2061.56	15743.00	678.00
22.	Rajasthan	190471.00	17605.37	59941.00	95018.00
23.	Sikkim	448.70	348.25	10118.00	273.00
24.	Tamil Nadu	66039.00	17347.41	7657.00	3331.00
25.	Tripura	5616.97	3925.83	-2467.00	2100.00
26.	Uttar Pradesh	146898.97	63465.32	30702.00	19890.00
27.	Uttarakhand	2291.88	1521.59	3474.00	2439.00
28.	West Bengal	19091.00	39450.71	63645.00	127.00
29.	Andaman and Nicobar	211.76	737.26	1033.00	0.00
30.	Dadra and Nagar Haveli	14.92	0.00	1384.00	0.00
31.	Daman and Diu	0.00	0.00	506.00	0.00
32.	Lakshadweep	103.92	0.00	489.00	0.00
33.	Pondicherry	900.00	0.00	-430.00	0.00
	TOTAL	1099365.72	585955.72	891935.00	398788.00

MR. CHAIRMAN : Are there any supplementaries? Shri Mukhtar Abbas Naqvi.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह काफी विस्तार से दिया है, मैं इसमें केवल स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि किन-किन राज्यों ने इस पूरी योजना पर खर्च किया। मंत्री जी ने बताया है कि किस राज्य ने 0 प्रतिशत खर्च किया, किसने कितना खर्च किया। उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि निगरानी के लिए जो बैठकें होती हैं, जिनमें NLM की बात है, PRC की बात है, NQM की बात है, इसके साथ ही महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात भी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने इन योजनाओं की निगरानी के लिए, जिन राज्यों में ये योजनाएं लागू नहीं हो पा रही हैं, उसके

लिए राज्य स्तर, जिला स्तर और केंद्रीय स्तर पर अब तक कितनी बैठकें कराईं हैं या हुई हैं और उन बैठकों का क्या निष्कर्ष निकला है? माननीय मंत्री जी इसके बारे में बताएं कि आज तक कितनी बैठकें हुईं?

श्री जयराम रमेश : सभापति जी, क्या यह सवाल उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है या सारे देश के बारे में पूछा गया है?

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : मेरा प्रश्न सारे देश के बारे में है।

श्री जयराम रमेश : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों के स्तर पर एक अलग निगरानी समिति होती है, इसके अलावा हम मंत्रालय के द्वारा भी जो निगरानी करते हैं, उसमें स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा मेरे स्तर पर भी, जो खर्च होता है, हम राज्यों को अलग-अलग ध्वज वाहिनी कार्यक्रमों के लिए जो पैसा या धनराशि देते हैं, उस पर क्या प्रगति हो पा रही है, हम अधिकारियों और मंत्रियों के साथ इस पर बातचीत करते हैं। यह एक सिस्टम बनाया गया है। मैं यह जरूर कह सकता हूं **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : आप इन योजनाओं की निगरानी के लिए **...(व्यवधान)...** आपकी लास्ट मीटिंग कब हुई है? **...(व्यवधान)...** हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन है **...(व्यवधान)...**

श्री जयराम रमेश : आज सुबह ही मीटिंग हुई है। मैं कल झारखंड में था और झारखंड के उप मुख्य मंत्री के साथ मेरी बैठक हुई थी। अगर मैं आपको अपना ट्रैवल प्लान भेज दूं तो आपको पता चल जाएगा **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सभापति जी, माननीय मंत्री जी का ट्रैवल प्लान नहीं चाहिए **...(व्यवधान)...** मेरा बहुत छोटा-सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि केंद्रीय योजनाओं की निगरानी के लिए कब मीटिंग हुई?

श्री सभापति : आप जवाब सुन लीजिए।

श्री जयराम रमेश : आपका प्रश्न स्पेसिफिक नहीं है। आप पूछ रहे हैं कि मैंने कब निगरानी की? मैं आपको बता रहा हूं कि मैं रोज निगरानी करता हूं। मैंने आज सुबह ही झारखंड के बारे में **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : मैं पूछ रहा हूं कि आखिरी निगरानी की बैठक कब हुई? **...(व्यवधान)...** यह मेरा सीधा-सीधा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मंत्री जी अपने जवाब से घुमा रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री जयराम रमेश : सभापति जी, अगर मैं सही समझूं तो माननीय सदस्य का सवाल यह है कि District-level Vigilance Monitoring Committee की मीटिंग कब हुई? माननीय सदस्य आप यह पूछिए, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल मोनिटरिंग कमेटी **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सभापति जी, मैं स्टेट लेवल की कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी और सैंट्रल लेवल की कमेटी के बारे में भी पूछ रहा हूं, लेकिन आप एक भी नहीं बता पा रहे हैं **...(व्यवधान)...**

श्री जयराम रमेश : ठीक है, लेकिन आप अभी असली मुद्दे पर आए हैं **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : हम शुरू से ही असली मुद्दे पर हैं।

श्री जयराम रमेश : सभापति जी, इन्होंने District-level Vigilance Monitoring Committee की बैठक के बारे में प्रश्न पूछा है। हम समिति का गठन करते हैं **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : आप बता नहीं पा रहे हैं **...(व्यवधान)...** आपको समझ नहीं आ रहा है **...(व्यवधान)...** आप लिख कर भेज दीजिए **...(व्यवधान)...**

MR CHAIRMAN : Stop interrupting please, Mr. Naqvi. बैठ जाइए **...(व्यवधान)...**

श्री जयराम रमेश : आप सुनिए तो सही **...(व्यवधान)...** बैठक बुलाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। यह बात सही है कि कई राज्यों में निगरानी समितियों की बैठक नहीं बुलाई गई है। मैंने राज्यों को बार-बार ख़त लिखा है **...(व्यवधान)...**

श्री बलबीर पुंज : कौन-कौन से राज्य हैं? **...(व्यवधान)...**

श्री जयराम रमेश : सुनिए तो सही **...(व्यवधान)...** ऐसा कोई राज्य नहीं है, जहाँ पर सही समय पर जितनी मीटिंग होनी चाहिए, हुई हैं। इसमें सभी राज्य सरकारें दोषी हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। कोई भी ऐसा एक राज्य नहीं है, जहाँ पर सही वक्त पर, सही ढंग से निगरानी समिति की बैठक जिला स्तर और राज्य स्तर पर हुई हो। कोई ऐसा राज्य नहीं है, परन्तु मैंने आपको कहा है कि जिम्मेदारी जिले के स्तर पर और राज्य के स्तर पर राज्य सरकारों और जिलाधिकारियों की होती है। मैंने बार-बार ख़त लिखा है, मैंने बार-बार राज्य सरकारों से कहा है कि वे इन समितियों की बैठक बुलाएँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने यह निर्णय भी लिया है कि कुछ नये कार्यक्रम, मिसाल के तौर पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ये निगरानी समिति में जोड़े जाएंगे, परन्तु अफसोस की बात है कि कोई राज्य सरकार इन समितियों की बैठक को गम्भीरता से नहीं लेती है। मैं एक बार फिर सदस्यों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आज ही सारे मुख्य मुत्रियों और ग्रामीण विकास मंत्रियों से फिर से निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द वे निगरानी समितियों की बैठक बुलाएँ और अगर तीन महीने के अंदर ये बैठक नहीं बुलाई जाएँ, तो अगले फंड रिलीज में हम इसको जरूर विचार में लेंगे।

MR. CHAIRMAN : Thank you. Now, Shri Derek O'Brien.

श्री सुखेन्दु शेखर राय : सर, मंत्री धमकी दे रहे हैं। It is a veiled threat. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN : Please. ...(*Interruptions*)...

श्री सुखेन्दु शेखर राय : अगर इम्प्लिमेंट नहीं हुआ, तो क्या विचार करेंगे? **...(व्यवधान)...** हमारा पैसा हमको दे रहे हैं **...(व्यवधान)...** हमारा पैसा हमको दे रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN : Please resume your seats. ...(*Interruptions*)... आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...**

श्री सुखेन्दु शेखर राय : हमारा पैसा हमको दे रहे हैं **...(व्यवधान)...** हमारा पैसा हमको दे रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN : Please sit down. ...(*Interruptions*)... Allow Mr. O'Brien to ask his question. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY : It is a veiled threat. ...(*Interruptions*)... He should not. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN : Please go ahead. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH : Sir, this is not a veiled threat. On the one hand, Members are agitating. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY : Sir, actually, it is not a veiled threat; it is a direct threat. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN : Mr. O'Brien, are you asking your question?

SHRI DEREK O'BRIEN : Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN : Please ask the question. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY : It is a direct threat.

SHRI JAIRAM RAMESH : Sir, if States do not perform, the money cannot be released. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY : It is our money. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN : Sir, before I ask question, I would like to quote just one line from the answer. "As per the revised release mechanism, Central assistance is being released after deducting the unspent balance available with the States."

Sir, whether due to delayed release of funds by the Central Government under different flagship programmes, the State Government are facing severe constraints on implementing projects in a definite timeframe, which enables the Central Government to seemingly make this the lame excuse to cut the allocation on the plea of unspent balance.

Sir, this is a classic case of a step-motherly attitude being shown to the States for no fault of the States by the Central Government.

SHRI JAIRAM RAMESH : Sir, when the States do not submit the Utilization Certificates on time, when the States do not submit Audit Reports on time, the Central Government cannot overlook these basic requirements and release the funds. The States are fully aware that before funds are released, the Utilization Certificates have to be given, and, the Audit Reports have to be submitted. Once the Utilization Certificates are submitted and the Audit Reports are given, there has been no delay in the release of

funds. There is a requirement for the second time release that they must spend a minimum of 60 per cent of the funds that have already been released. The State Governments are fully aware of all these stipulations and requirements. I can assure the hon. Member that there has been no delay in the release of funds. Where there has been time taken in release of funds is when the Utilization Certificates have not been submitted, when Audit Reports have not been submitted. When all these stipulations have been met, no State Government has suffered for want of funds including West Bengal. I would like to inform the hon. Member that if only he takes the trouble of talking to his own colleague, the Minister of Rural Development in the Government of West Bengal, he will realize that there has been no delay in the release of Rural Development funds.

SHRI DEREK O'BRIEN : My question is regarding the States. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN : Just a minute. Please. No, no. Mr. O'Brien, that is enough. ...(*Interruptions*)... Mr. Tapan Kumar Sen.

SHRI TAPAN KUMAR SEN : Sir, it is, indeed, a matter of great concern. The flagship programmes are particularly meant for improving the quality of life of people living in the rural India or of people who are in severe distress. It is not just about *Roti, Kapda aur Makaan.* It is about *Roti, Kapda, Makaan, Sarak*, and also about cultivation. Such a big amount remains unspent. Now, I am not making any politics out of it. There is a system you have told about, which is being monitored etc. Still that problem remains. And if you take note of BIMARU States, the amount of unspent money is much more than others. The people there really need resources. It is not that the people are having enough jobs, so they need not go in for the MGNREGA. It is not that in many States roads are very fine and they don't need your *Gram Sadak Yojana.* It is not like that. Despite all the systems in place, this is continuing. Will you go out of the way to put in some system, which is simplified, and, at the same time, guard against the misuse or abuse of the funds. I think something else is required to be done after experiments with the present system, which is in place, and the whole scheme, which is being developed to benefit the people, are not able to actually spend the money. I want to know whether the hon. Minister is considering review of the whole procedure or mechanism only to ensure that the money that goes there is spent and to create a deterrent against not spending the money.

SHRI JAIRAM RAMESH : Sir, the hon. Member is very well aware that under the current federal structure, the Central Government provides the funds for rural development programmes which are broadly defined to include water supply and

sanitation. In 2012-13, about 99,000 crore rupees are being given to the State Governments for rural development programmes. The responsibility for spending money on these programmes is entirely that of the State Governments. This is the federal structure. Sir, it is true that the ability of the States to spend this amount of money in the time span in which it is meant for is often not very, very visible. There are very many reasons for this. They may be administrative capacity, technical capacity, audit requirements and the need for bringing utilisation certificates. In today's environment, one wants to have transparency and accountability. You can't always allow a single tender because you can never wish away the possibility of the tender being manipulated.

So, you have to go for competitive bids. There are very many practical problems in the field. I accept the point that we must work with the State Governments to help them expand and improve their capacity to spend money. There is no shortage of money. There is no shortage of resources. But the real problem is in the ability of the States to spend the money, particularly States like Bihar, Jharkhand, Odisha, Assam, West Bengal for some programmes, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Largely in Central and Eastern India, the administrative and technical capacity to spend money quickly in a transparent and accountable manner needs to be strengthened. And I am working with the State Governments to ensure that this happens sooner rather than later.

Vacancy in Appellate Tribunal for Foreign Exchange

*224. DR. CHANDAN MITRA : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the position of Chairperson is vacant at the Appellate Tribunal for Foreign Exchange;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether Government is aware that no benches of the Tribunal have been constituted to exercise its jurisdiction;

(d) whether Government intends to appoint a Chairperson and any other member to the Tribunal; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI ASHWANI KUMAR) : (a) and (e) A Statement is laid on the Table of the House.